रूसी तकनीशियनों का दौरा

*228. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उद्योगो की स्थापना करने में भारतीय उपकरणों के उपयोग और भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की क्षमता का अध्ययन करने के लिये जनवरी, 1975 मे रूसी तकनीशियनो के एक दल ने भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री द्वारा दिये गये निमंत्रण पर रूस के भारी, विद्युत और परिवहन उद्योग मंत्री श्री वी० एफ० ज़िगालिन, और विशेषज्ञो के दो दलो ने जनवरी/फ़रवरी, 1975 मे भारत का दौरा किया था । दलों ने भारत मे अपने प्रवास के दौरान भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के हरिद्वार एकक, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, बोकारो इस्पात परियोजना और सरकारी क्षेत्र के दो अन्य एककों का भी दौरा किया । दौरे का उद्देश्य रूस की सहायता से बनी परियोजनाओं की क्षमताओ का पूर्ण उपयोग से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं जैसे हिस्से-पुर्जों और सामान की सप्लाई सन्तुलन संयत्र और मशीनों की आवश्यकता पर बातचीत करना था । दौरे का उद्देश्य यह पता लगाना भी था कि सरकारी क्षेत्र के ये उद्यम रूस द्वारा तीसरे देशों में स्थापित की जा रही परियोजनाओं के लिये कितने उपकरणों की सप्लाई कर सकते हैं । बातचीत के परिणामस्वरूप, नई दिल्ली में 10 फ़रवरी, 1975 को भारत और सोवियत संघ ने एक सलेख (प्रोटोकोल) पर हस्ताक्षर किए ।

Increase in Number of Adivasi Welfare Centres

*229. SHRI BHAGIRATH BHANWAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the number of Adivasi Welfare Centres in the country is inadequate to fulfil the needs;

(b) the total number of centres existing at present, Statewise; and

(c) the steps proposed to be taken to increase their number and bring efficiency into their working?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): (a) to (c) There is no Centrally sponsored programme of Adivasi Welfare Centres. However, the scheme of tribal development blocks had 504 units by the end of the Fourth Five Year Plan covering broadly those areas which had more than two-thirds tribal population. This coverage was not considered adequate. In the Fifth Plan all areas with more than 50 per cent concentration are being covered under the Integrated Tribal Development Projects. It is expected that now about seventy-five per cent of the country's total tribal population will be covered as against about forty per cent in the earlier programmes. With a view to ensure effective implementation, the States have been requested to review the administrative arrangements and streamline them.